भारत मे भविष्य की रूपरेखा–कौशल विकास

Sweta kumari
Assistant professor at St Paul college

सार: कौशल विकास को किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु रीढ की हड्डी के रूप में देखा जा सकता है। भारत के कौशल विकास को बढ़ाता देकर देश की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। हालांकि बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाये गए है परन्तु इसका बहुत फायदा अभी दिखायी नही दे रहा है इसलिए जरूरत है इसकी रफतार को तेज करने की तथ युवाओं को इसमे आकर्षित करने की।

भूमिका : कौशल विकास के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे उत्पादकता तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है जिससे गरीबी कम करने में मदद मिलती है। भारत में युवाओं कि कुल आबादी 34.33% के बराबर है इससे इस आबादी का सही उपयोग करने के लिए कौशल का विकास करना बहुत जरूरी है। क्योकि इसी से भविष्य कि रूपरेखा तैयार होती है।

देश कि 70.77 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है इसलिए ग्रामीण इलाको में कौशल का प्रशिक्षण देना तथा उनके कौशलो में सुधार करना ही आज के समय में सबसे बड़ी चुनौति है। लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाए गए है। कौशल संपन्न बनाए जाने वाले लोगों कि संख्या अधिक है जिससे नए उपाय कि आवश्यकता है कौशल विकास के समूचे माहौल को सुदृढ करने के लिए। इसके परमपरागत प्रणाली के साथ साथ नए ऑनलाइन तरीको को भी शमिल कर के मिश्रित प्रणाली कायम करना तथा उसे उद्यमिता से जोड़ना कौशल सपन्न बनाना इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए निजी क्षेत्र तथा उधोगो को भी इस कार्य में शामिल करना चाहिए। कौशल संबंधी प्रशिक्षण को व्यवसायिक शिक्षा का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है ताकि लोग इसकी आकांक्षा करे। महिलाओं को भी ध्यान रखा जाना चाहिए जो पारिवारिक जिम्मेवारियो सहित कई कारणो से नौकरी छोड़ देती है और बाद में फिर से नौकरी करना चाहती है। ऑनलाइन तरीकों को भी अपनाना ना केवल व्यवहारिक है बल्कि किफायती भी है इससे लोग अपनी पसंद कि व्यवसाय को चुन सकेंगे और उनकी पहुँच भी औपचारिक प्रशिक्षण प्रणाली तक होगी। सरकारी तथा निजी संगठनों द्वारा संचालित वर्तमान ऑनलाइन कौशल पाठ्यक्रमो को भी ऑनलाइंन कौशल प्लेटफार्म में शामिल किया जा सकता है साथ ही निजी क्षेत्रों कि भूमिका को बढ़ावा देना होगा। निजी क्षेत्र में कौशल सम्पन्न बनाने की प्रणाली को मजबूत करने में निजी क्षेत्र तथा उद्योगों कि भागीदारी का फायदा उठाया जा सकता है। उधोगो के साथ संपर्क बढ़ाने से कौशल सम्पन्न उम्मीदवारो को रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकते है इससे कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद

अपना कारोबार शुरू कर सकते है तथा नौकरी खोजने वालो की जगह नौकरी देने वाले बन सकते है। कौशल सपन्न नौजवानों में नियोजनीयता और तकनीकी जानकारी के बारे में भी बताया जाना चाहिए। साथ ही साफट स्किल्स का प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है। रोजगार खोजने वालो और रोजगार देने वालो का साझा पोटर्ल भी तैयार करना चाहिए जिससे दोनो को कही भी भटकना ना पड़े।

2. कई नई उभरती टेकनोलॉजी जैसे आर्टिफिशयल इंटेलिजेस (आईए, कृत्रिम बुद्धि) मशीन लर्निंग (एम सल) और रोवोटिकस 3 डी प्रिंटिश एनीमेशन इंटरनेट ऑफ शिंश्न (आई ओ टी) और बलॉकचेन व्यवसायिक मॉडलो और प्रकियाओ में नवसृजन ला रहे है। इस तरह लोगो को कौशल संपन्न बनाने और कौशल में सुधार करने के साथ नये कौशलो से संबंधित पाठ्यक्रम तथ प्रशिक्षण शुरू करना आवश्यक है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अवसरो का फायदा उठाने के लिए तैयार हो सकें। भारत को वैश्विक बाजार के लिए श्रमिक तैयार करने चाहिए ताकि भारतीय श्रमिक उधोगो के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडो और प्रक्रियाओं से युक्त होकर अधिक सख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनिया और विदेशी उप्पादको को भारत में विनिर्माण इकाइयों को आकर्षित कर सके जिससे भारत के मेक इन इंडिया आभियान में भी मदद मिलेगी।

इससे हम कृषि में कौशल विकास उद्यमिता के क्षेत्र में कौशल विकास तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास कि चर्चा करेगे। जिसने टेबल कि मदद लिया गया है। तथा प्रतिशत विधी का भी उपयोग हुआ है।

कृषि में कौशल विकास :

बढ़ती आबादी घटती उपजाऊ कृषि भूमि कम होते रोजगार तथा निवेश एवं बाजार के जोखिमो में कृषि क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के समक्ष कृषि को लाभकारी बनाने में बड़ी चुनौतिया खड़ी कर दी है। कृषि में कौशल विकास इन चुनौतियों का उचित समाधान बन सकता है किंतु वर्तमान परिप्रेक्षय में कृषि क्षेत्र में युवाओं का कौशल का कौशल विकास अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यस्था की मूख्य चुनौती से निपटाने में वे देश आगे है जिन्होने कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। सारणी से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत 21.9 करोड़ कार्यबल में केवल 0.3 प्रतिशत (7,54,000) ही कौशलपूर्ण है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र, गैर विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के लिए है यह आंकडा क्रमश 4 प्रतिशत, 2 प्रतिशत एवं 63 प्रतिशत है जो दर्शता है कि वर्तमान में कृषि में कौशल में भारी कमी है। आज कृषि आय बढाने की आवश्यकता है जो कृषि क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में किसानों के कौशल विकास से संभव है इसलिए परमपरागत कृषि के साथ–साथ अन्य उद्यम स्त्रोतो को पहचानना तथा उनमें किसानों का कौशल विकास जरूरी होगा।

सारणी संख्या–1

भारत में कुल कार्यबल में कौश पूर्ण शिक्षा का स्तर

(हजार में)

कौशलपूर्ण शिक्षा का स्तर	कृषि एवं संबंधित क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	गैर विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
औपचारिक डिग्री उपाधि	40	323	133	1542
औपचारिक डिप्लोमा सटिर्फिकेट (स्नातक से निम्म स्तर)	427	1273	471	3491
औपचारिक डिप्लोमा सटिर्फिकेट (स्नातक से उच्च स्तर)	287	341	265	1918
कुल प्रशिक्षित	754	1937	869	6951
कुल कार्यबल का प्रतिशत	0.3	4	2	6.3

स्रोत : राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, नीति आयोग, भारत सरकार (2013)

उद्यमिता के क्षेत्र में कौशल विकास :

उद्यमिता कौशल और ज्ञात किसी भी राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के कारकों में से एक है। किसी भी उद्यम के सफल संचालन व बाजार में उपभोक्ताओं की जरूरत और मांग के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है क्योंकि कोई भी उद्योग, व्यवसाय या व्यापार बिना कुशल एवं दक्ष मानव संसाधनों के अभाव में विकसित नहीं किया जा सकता है। उद्यमिता तथा कौशल विकास एक दूसरे के पूरक है। भारत की आर्थिक समीक्षा 18–19 के अनुसार उद्यमिता पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय सूक्ष्म, लघु और अध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देकर उन्हें अधिक उत्पादक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में विभिन्न सुधारात्मक कार्य पर चर्चा की गई है। भारत जैसे देश जहां अधिकतर जनसंख्या कार्यशील है उन्हें शिक्षा कौशल विकास और प्रशिक्षण से बेहतर मानव संसाधन बनाया जा सकता है जिससे बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक बुराईयों का भी समाधान किया जा सकता है जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है।

सारणी संख्या–2 से यह समझ सकते है कि भारत का कुल कार्यबल में से केवल 23 प्रतिशत ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है जबकि विकसित देशों में यह प्रतिशत क्रमश 68% 75% 52% 80%

96% है। अत हम देखते है कि दक्षिण कोरिया जिसमें 96: प्रशिक्षित कार्यबल है इस तरह से यदि हम देखे तो भारत बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। भारत को इस स्थिति से निकालने के लिए भारत सरकार ने काफी योजनाए जैसे–स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अटल इनोवेशन मिशन इनवयूवेशन सेटर (AIC) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2.0) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी अनेक योजना चलायी गई है।

सारणी संख्या–2

क्र0 स0	देश/अर्थव्यवस्था	कुल कार्यबल में से औपचारिक रूप से प्रशिक्षित (प्रतिशत)
1.	भारतत	2.3
2.	यूनाइटेड किंगडम (UK)	69
3.	जर्मनी	75
4.	अमेरिका (USA)	52
5.	जापान	80
6.	दक्षिण कोरिया	96

स्वस्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास : नेशल हैल्थ प्रोफाइल 2018 में 31 मार्च 2017 को देश में कुल 58 लाख स्वास्थ्यकर्मियो के होने कि बात कही गई जिनमें सबसे अधिक संख्या नर्सो कि है और सबसे कम संख्या महिला हैल्थ विजिटर्स की है जिसे नीचे की तालिका से समझा जा सकता है।

स्वास्थ्यकर्मि	संख्या
एलौपैथिक डॉकटर	10 लाख
आयुव डॉक्टर	77 लाख
नर्स	19 लाख
फार्मासिस्ट	9 लाख

ए एन एम	84 लाख
डेंटिस्ट	25 लाख
महिला हैल्थ रिजिटर्स	56 लाख

स्त्रोत :– नेशनल हैल्थ प्रोफाइल –2018

राष्ट्रीय स्वस्थ्य परिदृश्य 2018 में भारत में स्वास्थ्यकर्मियों की अवश्यकता का 58 लाख अनुमान लगाया है। भारत के कौशल संपन्न स्वास्थ्यकर्मियो की उपलब्धता बढ़ाने के उददेश्य से न्यू इंडिया/75 के लिए नीति आयोग की 2018–22 की राजनीतिक योजना में 2022–23 तक जनसंख्या क्षेत्र में रोजागर के 15 लाख अवसर काउंसिल (एस. एस. एस सी) ने अगले दशक में स्वस्थ्य देखभाल से संबंधित क्षेत्र में 48 लाख लोगो को चरणबद्ध तरीके से कौशल सपन्न बनाने का लक्ष्य रखा है।

कौशल विकास को किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु रीढ की हड्डी के रूप में देखा जा सकता है। भारत के कौशल विकास को बढ़ावा देकर देश कि आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। हालांकि बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाये गए है परन्तु इसका बहुत फायदा अभी दिखायी नही दे रहा है इसलिए जरूरत है इसकी रफतार को तेज करने की तथ युवाओं को इसमे आकसिर्त करने की ।

संदर्भ सूची :

1. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन बुकलेट, कौशल विकास और उषमशीलता मंत्रालय
2. नेशनल हैल्थ प्रोफाइल –2018
3. राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, नीति आयोग
4. कुरूक्षेत्र
5. प्रतियोगिता दर्पण
6. आर्थिक समीक्षा 2018,19
7. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय